

भारत सरकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-29  
सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं

29. श्री संगम लाल गुप्ता:  
श्री रामदास तडस:  
श्री सी.पी. जोशी:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने पद स्वीकृत हैं;
- (ख) उक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और प्रशिक्षुओं और संस्थानों को क्रमशः आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार गत तीन वर्षों से आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवंटित नहीं कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ में, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में आईटीआइज में स्वीकृत सीटों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	आईटीआई में सीटों की संख्या	पीएमकेवीवाई 2.0 में सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या
1	महाराष्ट्र	302728	53545	356273
2	राजस्थान	349416	66860	416276
3	उत्तर प्रदेश	771944	151060	923004
	कुल	1424088	271465	1695553

(ख से ड)

- विद्यमान सरकारी आईटीआइज का मॉडल आईटीआइज में उन्नयन और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास के तहत आवंटित निधियों का विवरण अनुबंध - क में दिया गया है।
- विश्व बैंक सहायित व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) और स्ट्राइव के तहत आवंटन का विवरण अनुबंध - ख में दिया गया है।
- पीएमकेवीवाई 2.0 योजना के तहत संवितरित निधि का ब्यौरा अनुबंध - ग में दिया गया है।

श्री संगम लाल गुप्ता, श्री रामदास सी. तडस, श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा 18.11.2019 को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न राज्यों में कौशल विकास के लिए आईटीआइज के वित्तपोषण हेतु निम्नलिखित योजनाएं निरूपित की हैं:

- 1. विद्यमान सरकारी आईटीआइज का मॉडल आईटीआइज में उन्नयन:** राज्य में विद्यमान सरकारी आईटीआइज को मॉडल आईटीआइ में उन्नयन का कार्य हाथ में लिया गया है जिससे कि इसे सर्वोत्तम पद्धतियों और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और स्वीकार्य तथा प्रभावी उद्योग संबंधों को प्रदर्शित करने वाली संस्था के रूप में विकसित किया जा सके। प्रत्येक आईटीआइ के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) सोसाइटी जिसका अध्यक्ष उद्योग से होता है बनाई गई है, और इसे आईटीआइ स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए सक्षम बनाया गया है। इस योजना का दिसंबर 2014 में अनुमोदन किया गया था जिसकी कुल लागत रु. 300 करोड़ है। योजना की क्रियान्वयन अवधि 3 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 तक थी। इस योजना को अब स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा दिनांक 09.08.2018 को सचिव (एमएसडीई) का अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल रु. 300 करोड़ की लागत के साथ मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है। जारी निधियों का विवरण **अनुबंध क/1** में दिया गया है।
- 2. वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास:** इस योजना में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों के लोगों के निकटतर कौशल विकास अवसंरचना सृजित करने की परिकल्पना की गयी है। योजना में 10 राज्यों के 47 वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों को शामिल किया गया है। योजना की कुल लागत 407.85 करोड़ रुपए थी तथा कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च, 2019 तक है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 10 राज्यों के 47 जिलों में प्रति जिला एक आईटीआइ की दर से 47 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) हेतु बुनियादी ढांचा सृजित करने तथा 9 राज्यों के 34 जिलों में प्रति जिला 2 एसडीसीज की दर से 68 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसीज) के लिए बुनियादी ढांचा सृजित करने की परिकल्पना की गयी है। कुल आवंटित राशि अर्थात् रु. 404.24 करोड़ में से रु. 259.35 करोड़ की राशि जिसमें रु. 62.65 करोड़ राज्यों का हिस्सा शामिल है, दिनांक 01.07.2019 तक इस उद्देश्य के लिए राज्यों को जारी कर दिया गया है। जारी निधियों का विवरण **अनुबंध क/1** में दिया गया है। योजना का अनुमोदन 31 मार्च, 2020 तक था।

उपरोक्त योजनाओं में प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र का कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल नहीं है।

**विद्यमान सरकारी आईटीआइज का मॉडल आईटीआइज में उन्नयन**

योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का विवरण, राज्यवार तालिका में नीचे दिया गया है: -

(रु. लाख में)							
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईटीआई का स्थान	केंद्रीय आबंटन	वि.व. 16-17 में जारी निधियां	वि.व. 17-18 में जारी निधियां	वि.व. 18-19 में जारी निधियां	कुल
1	आंध्र प्रदेश	आईटीआई गजुवाका	700.00	175.00			175.00
2	असम	आईटीआई जोरहट	783.00		195.75		195.75
3	अरुणाचल प्रदेश	आईटीआई यूपिया	392.00	98.00		97.75	195.75
4	बिहार	आईटीआई मरोहारा	700.00				0.00
5	छत्तीसगढ़	आईटीआई भिलाई	700.00	175.00			175.00
6	चंडीगढ़	आईटीआई चंडीगढ़	1000.00			150.00	150.00
7	दिल्ली	आईटीआई पूसा	590.00	295.00			295.00
8	गोवा	आईटीआई पणजी	350.00	87.50			87.50
9	गुजरात	आईटीआई दशरथ	637.00	91.65			91.65
10	हरियाणा	आईटीआई गुडगांव	700.00	350.00			350.00
11	हिमाचल प्रदेश	आईटीआई नालागढ़	639.00	130.55			130.55
12	झारखंड	आईटीआई रांची	700.00				0.00
13	कर्नाटक	आईटीआई बेंगलुरु	700.00			136.00	136.00
14		आईटीआई होन्नावर	350.00			175.00	175.00
15	केरल	आईटीआई कलमसरी	700.00	175.00		280.00	455.00
16	मध्य प्रदेश	आईटीआई भोपाल	700.00	276.5			276.50
17	महाराष्ट्र	आईटीआई नासिक	629.30				0.00
18	ओडिशा	आईटीआई बारबिल	497.00	198.8			198.80
19	पंजाब	आईटीआई रूपनगर	700.00	173.00			173.00
20	पुडुचेरी	आईटीआई मेट्टुपालयम (पुरुष)	350.00			175.00	175.00
21	राजस्थान	आईटीआई उदयपुर	350.00	46.30		0.00	46.30
22	सिक्किम	आईटीआई नामचि	450.00	49.50			49.50
23	तमिलनाडु	आईटीआई कोयंबटूर	700.00				0.00
24	त्रिपुरा	आईटीआई इंदिरानगर (डब्ल्यू)	720.00		248.94		248.94
25	तेलंगाना	आईटीआई मल्लेपल्ली	700.00				0.00
26	उत्तर प्रदेश	आईटीआई मेरठ	700.00	154.00		280.00	434.00
27		आईटीआई वाराणसी	630.00	157.50		157.50	315.00
28	उत्तराखंड	आईटीआई जगजीतपुर, हरिद्वार	525.00			88.75	88.75
29	पश्चिम बंगाल	आईटीआई दुर्गापुर	700.00			185.00	185.00
कुल			17992.30	2633.30	444.69	1725.00	4802.99

\* केंद्र और राज्य का अंश 70:30 के अनुपात में शामिल है (पूर्वोत्तर में यह अनुपात 90:10 है, विधायिका के बिना संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100% है)

**वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास**

योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का विवरण, राज्यवार तालिका में नीचे दिया गया है: -

(रु. लाख में) (केवल केंद्र का हिस्सा)						
क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय आवंटन	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में जारी निधियां			कुल
			वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	
1	आंध्र प्रदेश	650.95		412.92		412.92
2	तेलंगाना	628.60				0.00
3	बिहार	6633.43		396.90		396.9
4	छत्तीसगढ़	5702.08	1646.59			1646.59
5	झारखंड	11252.17	300.00	3031.34	1072.21	4403.55
6	मध्य प्रदेश	628.60				0.00
7	<b>महाराष्ट्र</b>	<b>1408.69</b>				<b>0.00</b>
8	ओडिशा	3793.94	274.95			274.95
9	उत्तर प्रदेश	628.60				0.00
10	पश्चिम बंगाल	628.60		171.84		171.84
	<b>कुल</b>	<b>31955.65</b>	<b>2221.54</b>	<b>4013.00</b>	<b>1072.21</b>	<b>7306.75</b>

श्री संगम लाल गुप्ता, श्री रामदास सी. तडस, श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा 18.11.2019 को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध

परियोजना अनुभाग निम्नलिखित दो योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:

1. विश्व बैंक सहाय्यित व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी): इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 400 सरकारी आईटीआइज के उन्नयन का कार्य शामिल हैं। यह योजना सितम्बर, 2018 में बंदकर दी गई थी।
2. स्ट्राइव विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित नयी केंद्रीय परियोजना है जिसकी कुल लागत रु. 2200 करोड़ है। परियोजना की अवधि 5 वर्ष है और इसकी समाप्ति तिथि नवम्बर 2022 है।
3. निधियों का उपयोग राज्यों द्वारा योजनाओं (वीटीआईपी और स्ट्राइव) के तहत चुने गए आईटीआइज के लिए किया गया।

निधियां पिछले तीन वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप जारी गईं।

विवरण अनुबंध ख/। में संलग्न किया गया है।

प्रतापगढ़ को वीटीआईपी तथा स्ट्राइव योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) योजना के तहत राज्यवार जारी निधियां

लाख में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र की आबंटित/जारी निधियां		
	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	55.91	22.04	19.00
उत्तर प्रदेश	265.08	0.00	0.00
कुल	320.99	22.04	19.00

औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) योजना के तहत राज्यवार जारी निधियां

करोड़ में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवंटित/जारी केंद्रीय निधियां
1	महाराष्ट्र	0.38
2	राजस्थान	0.44
3	उत्तर प्रदेश	3.76
	कुल योग	4.58

श्री संगम लाल गुप्ता, श्री रामदास सी. तडस, श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा 18.11.2019 को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (क), (ख) तथा (ड) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध

पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों (2016-17; 2017-2018 तथा 2018-19) में प्रशिक्षणार्थियों तथा संस्थानों को संवितरित कुल निधियां

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
संस्थानों को संवितरित निधि	146.00	1,658.51	1,117.68	2,922.19
प्रशिक्षणार्थियों को संवितरित निधि	-	33.90	151.03	184.93

\*सभी आंकड़े करोड़ में हैं

\*उपरोक्त संवितरण में अभ्यर्थियों के प्रशासन शुल्क तथा बीमा को शामिल नहीं किया गया है।

पिछले तीन वर्षों (2016-17; 2017-2018 तथा 2018-19) में यूपी (प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र हेतु अलग से भी), राजस्थान तथा महाराष्ट्र में पीएमकेके के तहत संवितरित कुल निधियां

क्र.सं.	राज्य	पीएमकेके के तहत संवितरित निधियों का विवरण		
		वि.व.-16-17	वि.व.-17-18	वि.व.-18-19
1	राजस्थान	2.270	5.294	3.775
2	महाराष्ट्र	0.908	5.374	5.272
3	उत्तर प्रदेश	7.979	17.307	3.662
	प्रतापगढ़, यूपी	0.22	0.17	

\*सभी आंकड़े करोड़ में हैं।

\*\*\*\*\*